संपादकीय

भारतीय लोकतंत्र में चुनावी सरगर्मी के बीच शिक्षा पर राजनैतिक विमर्श लगभग शून्य है। चुनावी रैलियों और भाषणों में शिक्षा के मुद्दे नदारद हैं। हालांकि तमाम राजनैतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं और शिक्षा पर भी अपनी घोषणाएं एवं प्रतिबद्धताएं जाहिर की हैं। शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं यह घोषणा पत्र, संक्षिप्त सार यहां प्रस्तुत है।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा को महत्त्वपूर्ण मानते हुए शिक्षा को 'भावी पीढ़ियों के लिए संस्कृति, धरोहर और इतिहास तथा भारत की जीवनशक्ति पर गर्व करने के लिए जरूरी' बताते हुए शिक्षा में 'नए प्राण फूंकने और पुनः व्यवस्थित करने' की बात की है। साथ ही घोषणा पत्र में शिक्षा के जरिए 'राष्ट्रीय अस्मिता एवं राष्ट्रभक्ति' विकसित करने की बात की है। इसमें माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण और कौशल के विकास पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रियाओं की पूरी तरह समीक्षा करने की बात भी कही गई है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में अपनी उपलब्धियों के साथ शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारत की शिक्षा व्यवस्था को 'दुनिया में बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था' बनाने के साथ 'सर्व शिक्षा अभियान' को 'श्रेष्ठ शिक्षा अभियान' में बदलने की बात कही गई है। साथ ही शिक्षा के अधिकार कानून को और मजबूती देने का वायदा किया है जिसमें पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं, वांछित शिक्षक-बालक अनुपात एवं शिक्षक प्रशिक्षणों पर जोर देने की बात कही गई है। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन एवं ध्यान देने तथा माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन को अर्जित करने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। साथ ही निजी एवं राजकीय शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र नियामक व्यवस्था स्थापित करने की बात कही गई है।

आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र वर्तमान शिक्षा की दयनीय स्थिति के प्रति चिंता जाहिर करते हुए आम आदमी की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की बात करता है। इसके साथ ही बालिकाओं, पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले बच्चों और गरीब परिवार तथा वंचित समुदाय के बच्चों का संपूर्ण नामांकन, ड्रॉप-आउट रोकने, सीखने की उच्च गुणवत्ता और स्कूल में बच्चों के साथ भेदभाव रहित शिक्षा पर जोर देता है। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में संदर्भयुक्त पाठ्यचर्या और शाला प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी की बात कही गई है।

हम सिर्फ तीन ही पार्टियों का घोषणा पत्र देख पाए हैं। यह सिर्फ घोषणा पत्र हैं। सरकार बनने के बाद इन पर कितना अमल किया जाएगा, यह भविष्य ही बताएगा लेकिन तीनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र निराश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को देखकर लगता है कि यह अपने भगवाकरण के पुराने एजेण्डे पर ही लौटकर आएगी और इसके संकेत दे भी दिए गए हैं। कांग्रेस पिछले दस सालों में शिक्षा की बेहतरी के प्रयासों में असफल रही है। शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन में कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी, जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें रही हैं, वहां शिक्षा के अधिकार कानून को लागू होने के चार साल बाद भी गंभीर नहीं रही हैं। वर्तमान में शिक्षा की बड़ी समस्या - शिक्षा के बाजारीकरण एवं व्यावसायीकरण पर लगाम लगाने को लेकर तीनों ही पार्टियां मौन हैं और घोषणा पत्रों को देखकर लगता है कि देश की शिक्षा में मूलभूत बदलाव लाने में यह बेअसर ही होंगी। ◆